

## मौद्रिक नीति समीक्षा: RBI

### प्रलम्ब के लिये:

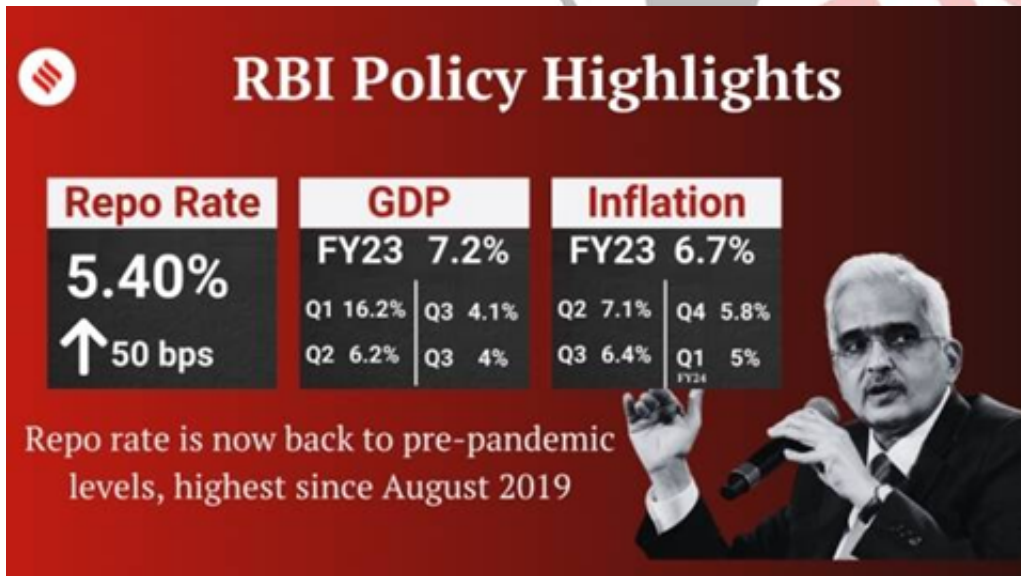
RBI, मौद्रिक नीति समिति (MPC), मौद्रिक नीति के साधन, RBI के वभिन्न नीतितगत रुख

### मेन्स के लिये:

मौद्रिक नीति, वृद्धि और विकास, मौद्रिक नीति और इसके उपकरण

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय रिज़र्व बैंक \(RBI\)](#) ने अपनी [मौद्रिक नीति समिति \(MPC\)](#) की समीक्षा में रेपो दरों में 50-आधार अंक की वृद्धि की घोषणा की, जिससे पछिल्ले तीन महीनों में संचयी दर में वृद्धि 140 आधार अंक तक हो गई थी।



## प्रमुख बढि

### प्रमुख दरें:

- पॉलिसी रेपो दर: 5.40%**
  - रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक) किसी भी तरह की धनराशिकी कमी होने पर वाणजियिक बैंकों को धन देता है। इस प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक प्रतभित्ति खरीदता है।
- स्थायी जमा सुवधि (SDF): 5.15%**
  - वस्तुतः इसे अधशेष तरलता (Surplus Liquidity) को समाप्त करने एवं बैंकिंग प्रणाली की समस्या को कम करने के एक उपकरण के तौर पर देखा जा रहा है।
  - यह रविरस रेपो सुवधि से इस मायने में अलग है कि इसमें बैंकों को फंड जमा करते समय संपार्श्विक प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- सीमांत स्थायी सुवधि दर: 5.65%**
  - MSF ऐसी स्थिति में अनुसूचति बैंकों के लिये आपातकालीन स्थिति में RBI से ओवरनाइट (रातों-रात) ऋण लेने की सुवधि है जब

अंतर-बैंक तरलता पूरी तरह से कम हो जाती है।

◦ इंटरबैंक लेंडिंग के तहत बैंक एक नश्चित अवधि के लिये एक-दूसरे को फंड उधार देते हैं।

- **बैंक दर: 5.65%**
  - यह वाणज्यिक बैंकों को धन उधार देने के लिये आरबीआई द्वारा वसूल की जाने वाली दर है।
- **नकद आरक्षण अनुपात (CRR): 4.50%**
  - CRR के तहत वाणज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास एक नश्चित न्यूनतम जमा राशि (NDTL) आरक्षण रखनी होती है।
- **वैधानिक तरलता अनुपात (SLR): 18.00%**
  - वैधानिक तरलता अनुपात या SLR जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जैसे एक वाणज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है।
- **अनुमान:**
  - **वर्ष 2022-23 के लिये GDP बढ़त: 2%**
    - यह सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) के अनुरूप है। GDP उपभोक्ताओं की आर्थिक गतिविधियों का परिणाम है। यह नज्दी खपत, अर्थव्यवस्था में सकल निवेश, सरकारी निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध वदेशी व्यापार (नरियात व आयात के बीच का अंतर) का योग है।
  - **वर्ष 2022-23 के लिये मुद्रास्फीति अनुमान: 6.7%**
    - मुद्रास्फीति एक नश्चित अवधि में कीमतों में वृद्धि की दर है। मुद्रास्फीति आमतौर पर एक व्यापक उपाय है जैसे की कीमतों में समग्र वृद्धि या किसी देश में रहने की लागत में वृद्धि।

## रेपो दर में बढ़ोतरी

- भले ही उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में अपने उच्चाल से कम हो गई हो, लेकिन यह असुवधाजनक रूप से उच्च और लक्ष्य के ऊपरी सीमा (6%) से ऊपर रहने की उम्मीद है।
- मुद्रास्फीति का ये उच्च स्तर MPC के लिये चिंता का विषय बना रहा क्योंकि RBI के अनुसार भारत सरकार का मुद्रास्फीति लक्ष्य (4% +/- 2%) है।
- यह उम्मीद की जाती है कि मुद्रास्फीति Q2 और Q3 (वित्त वर्ष 2022-23) में ऊपरी सीमा (6%) से ऊपर रहेगी।
- यह नरितर उच्च मुद्रास्फीति अपेक्षित मुद्रास्फीति को अस्थिर कर सकती है और मध्यम अवधि में विकास को नुकसान पहुँचा सकती है।
- मौद्रिक सुवधा का आहरण (मुद्रा आपूर्ति का वसितार) या बढ़ती दरें मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रख सकती हैं और मुद्रास्फीति के दूसरे दौर के प्रभाव को शामिल कर सकती हैं।
  - दूसरे दौर के प्रभाव तब प्रारंभ होते हैं जब मुद्रास्फीति मजदूरी और मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती है, जिससे मजदूरी-मूल्य सर्पिल (Spiral) होता है।

## रेपो रेट में वृद्धि से कर्जदारों और जमाकर्त्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव:

- यह होम लोन ग्राहकों और संभावित उधारकर्त्ताओं को प्रभावित करेगा, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऋण की दरों में वृद्धि होगी।
- यह उन निवेशकों को लाभान्वित करेगा, जो अपने धन को बैंक सावधि जमा में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि रेपो दर में वृद्धि के बाद जमा दरों में वृद्धि होने की उम्मीद होती है।
- जमा दर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में ऋण की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और बैंकों को अतिरिक्त धन जुटाने में भी मदद मिलेगी।

## तरलता:

- बैंकों के पास धन की उपलब्धता में सुधार करते हुए दरों में वृद्धि से **परणालीगत तरलता में धीरे-धीरे गरिबट आयेगी**।
- परणाली में पर्याप्त तरलता बनाए रखने के लिये आरबीआई विभिन्न परिपक्वता के **परिवर्तनीय रेपो दर (VRR)** और **परिवर्तनीय रिवर्स रेपो दर (VRRR)** संचालन के रूप में **दो-तरफा फाइन-ट्यूनिंग** उपाय को अपनाएगा।
  - **परिवर्तनीय दर संचालन** आमतौर पर परणाली में **मौजूदा नकदी को निकालकर धन प्रवाह को कम करने के लिये** किया जाता है।
  - केंद्रीय बैंक, इस परणाली में अधिशेष चलनधि को पुनर्संतुलित कर रहा है एवं नश्चित दर से इसे शीघ्र ही रिवर्स रेपो वडि के माध्यम से लंबी परिपक्वता की VRRR नीलामयियों में स्थानांतरित कर रहा है।

## मौद्रिक नीति ढाँचा:

- **उत्पत्ति:**
  - मई 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि देश की मौद्रिक नीतिगत ढाँचे को संचालित करने के लिये केंद्रीय बैंक को विधायी अधिदेश प्रदान किया जा सके।
- **उद्देश्य:**
  - ढाँचे का उद्देश्य वर्तमान और वकसति व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर नीतिगत (रेपो) दर निर्धारित करना तथा रेपो दर पर या उसके आस-पास मुद्रा बाजार दरों को स्थिर करने के लिये तरलता में सुधार करना है।
- **नीतिदर के रूप में रेपो दर का कारण:** रेपो दर में परिवर्तन मुद्रा बाजार के माध्यम से संपूर्ण वित्तीय परणाली में संचारित होता है, जो बदले में समग्र मांग को प्रभावित करता है।

- इस प्रकार यह मुद्रास्फीति और विकास का एक प्रमुख निर्धारक है।

## मौद्रिक नीति समिति (MPC):

- **उत्पत्ति:** संशोधन (2016 में) **आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB** के तहत केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।
- **उद्देश्य:** धारा 45ZB में कहा गया है कि "मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीति निर्धारण करेगी"।
  - मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंको के लिये बाध्यकारी होगा।
- **गठन: अधिनियम की धारा 45ZB के अनुसार MPC में 6 सदस्य होंगे:**
  - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक के पदेन अध्यक्ष के रूप में,
  - उप राज्यपाल, मौद्रिक नीति के प्रभारी के रूप में
  - केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी
  - केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्य।
    - नियुक्तियों की यह श्रेणी "अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम व्यक्तियों" से संबंधित होनी चाहिये।

## मौद्रिक नीति के उपकरण:

- रेपो दर
- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर
- चलनधिसमायोजन सुविधा (LAF)
- LAF कॉरडोर
- मुख्य चलनधि प्रबंधन उपकरण
- फाइन ट्यूनिंग संचालन
- रविर्स रेपो रेट
- बैंक दर
- नकद आरक्षण अनुपात (CRR)
- वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)
- ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO)

## वस्तुवादी मौद्रिक नीति

- **परिचय:**
  - वस्तुवादी मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के वस्तुवादी (बढ़ाने) पर केंद्रित है। इसे आसान मौद्रिक नीति के रूप में भी जाना जाता है।
  - इसे प्रमुख ब्याज दरों को कम करके लागू किया जाता है जिससे बाजार की तरलता (मुद्रा आपूर्ति) बढ़ जाती है। उच्च बाजार तरलता आमतौर पर अधिक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है।
  - जब RBI वस्तुवादी मौद्रिक नीति अपनाता है, तो यह रेपो, रविर्स रेपो, MSF, बैंक दर आदि जैसी नीतितरत दरों (ब्याज दरों) को कम करता है।
- **नहितार्थ**
  - बॉण्ड की कीमतों में वृद्धि और ब्याज दरों में कमी का कारण बनता है।
  - कम ब्याज दरें पूंजी निवेश के उच्च स्तर की ओर ले जाती हैं।
  - कम ब्याज दरें घरेलू बॉण्ड को कम आकर्षक बनाती हैं, इसलिये घरेलू बॉण्ड की मांग गिरती है और विदेशी बॉण्ड की मांग बढ़ जाती है।
  - घरेलू मुद्रा की मांग गिरती है और विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है, जिससे वनिमिय दर में कमी आती है। (घरेलू मुद्रा का मूल्य अब विदेशी मुद्राओं की तुलना में कम है)
  - कम वनिमिय दर के कारण निर्यात बढ़ता है, आयात घटता है और व्यापार संतुलन बढ़ता है।

## संकुचनकारी मौद्रिक नीति:

- **परिचय:**
  - संकुचनकारी मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करने (घटाने) पर केंद्रित है। इसे कठोर मौद्रिक नीति के रूप में भी जाना जाता है।
  - संकुचनकारी मौद्रिक नीति को प्रमुख ब्याज दरों में वृद्धि करके लागू किया जाता है जिससे बाजार की तरलता (मुद्रा आपूर्ति) कम हो जाती है। कम बाजार तरलता आमतौर पर उत्पादन और खपत को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसका आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
  - जब RBI संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाता है, तो यह रेपो, रविर्स रेपो, MSF, बैंक दर आदि जैसी नीतितरत दरों (ब्याज दरों) को बढ़ाता है।

■ **नहितार्थ:**

- संकुचनशील मौद्रिक नीति बॉण्ड की कीमतों में कमी और ब्याज दरों में वृद्धि का कारण बनती है।
- उच्च ब्याज दरें पूंजी निवेश के निम्न स्तर की ओर ले जाती हैं।
- उच्च ब्याज दरें घरेलू बॉण्ड को अधिक आकर्षक बनाती हैं, इसलिये घरेलू बॉण्ड की मांग बढ़ती है और विदेशी बॉण्ड की मांग गिरती है।
- घरेलू मुद्रा की मांग बढ़ती है और विदेशी मुद्रा की मांग गिरती है, जिससे वनिमिय दर में वृद्धि होती है। (घरेलू मुद्रा का मूल्य अब विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक है)
- उच्च वनिमिय दर के कारण निर्यात में कमी आती है, आयात में वृद्धि होती है और व्यापार संतुलन में कमी आती है।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs):

**प्रश्न. यदि भारतीय रज़िर्व बैंक एक वसितारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निरणय लेता है, तो वह नमिनलखिति में से क्या नहीं करेगा? (2020)**

वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन

2. सीमांत स्थायी सुवधि दर में बढ़ोतरी
3. बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती

**नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:**

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

**उत्तर: (b)**

- **वसितारति मौद्रिक नीति** आसान मौद्रिक नीति तब होती है जब केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहति करने के लिये अपने उपकरणों का उपयोग करता है। यह मुद्रा आपूर्ति तथा मांग को बढ़ाता है, ब्याज दरों को कम करता है इस प्रकार यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
- **वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)** एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग भारतीय रज़िर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों के निपिटान में तरलता का आकलन करने के लिये करता है। यह जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जिससे वाणज्यिक बैंक को नकद, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। यह मूल रूप से आरक्षण आवश्यकता है जिससे बैंकों से ग्राहकों को ऋण देने से पहले रखने की अपेक्षा की जाती है। एसएलआर बढ़ाने से बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक पैसा लगाते हैं और अर्थव्यवस्था में नकदी के स्तर को कम करते हैं। इसके विपरीत स्थिति में अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को बनाए रखने में मदद मिलती है। एसएलआर कम करने से बैंकों के पास अधिक तरलता बच जाती है जो बदले में अर्थव्यवस्था में विकास और मांग को बढ़ावा दे सकती है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- **सीमांत स्थायी सुवधि (Marginal Standing Facility- MSF):** वह सुवधि जिसके तहत अनुसूचित वाणज्यिक बैंक अपने 'वैधानिक तरलता अनुपात' (SLR) पोर्टफोलियो में निश्चित सीमा तक कमी (Dipping) करके ओवरनाइट सुवधि के तहत अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। एमएसएफ दर में वृद्धि के साथ बैंकों के लिये उधार लेने की लागत बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप उधार देने के लिये उपलब्ध संसाधन कम हो जाते हैं। **अतः कथन 2 सही है।**
- **रेपो दर या पुनर्खरीद दर** ब्याज की प्रमुख मौद्रिक नीति दर है जिस पर केंद्रीय बैंक या भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) तरलता समायोजन सुवधि (LAF) के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के बदले बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। बैंक दर वह ब्याज दर है जो आरबीआई अपने दीर्घकालिक ऋणों पर वसूल करता है। वसितारवादी मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई बैंकिंग क्षेत्र में तरलता बढ़ाने के लिये रेपो दर और बैंक दर को कम करता है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**

**प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नमिनलखिति पर वचिर कीजिये: (2015)**

बैंक दर

2. खुला बाज़ार परिचालन
3. सार्वजनिक ऋण
4. सार्वजनिक राजस्व

**उपर्युक्त में से कौन सा/से मौद्रिक नीति का/के घटक है/हैं?**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1 और 2
- (d) केवल 1, 3 और 4

**उत्तर: (c)**

- मौद्रिक नीति से तात्पर्य केंद्रीय बैंक की उस नीति से है जो मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर के प्रबंधन के लिये अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में मुद्रास्फीति, विकास आदि जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये करती है।
- भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) को मौद्रिक नीति के संचालन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है यह ज़िम्मेदारी भारतीय रज़िर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्पष्ट रूप से अनिवार्य है।
- मौद्रिक नीति के उपकरण/घटक नकद आरक्षण अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, रेपो दर, रविर्स रेपो दर, बैंक दर, चलनधि समायोजन सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा, खुले बाज़ार संचालन आदि हैं। **अतः 1 और 2 सही हैं।**
- सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक राजस्व राजकोषीय नीतिका हिससा है। **अतः 3 और 4 सही नहीं हैं।**

अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

प्रश्न. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि स्थिर जीडीपी वृद्धि और कम मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में ला दिया है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिये। (मुख्य परीक्षा- 2019)

[स्रोत: द हिंदू](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/monetary-policy-review-rbi-1>

